7.	हरियाणा	4576.57	3940.35
8.	हिमाचल प्रदेश	4746.00	4536.73
9.	जम्मू और कश्मीर	1795.95	सू० न०
10.	कर्नाटक	6167.87	4812.62
11.	केरल	1215.00	सू० न०
12.	मध्य प्रदेश	5512.96	5354.49
13.	महाराष्ट्र	7624.11	6321.10
14.	मणिपुर	573.65	सू० न०
15.	मेघालय	1164.07	सू० न०
16.	मिजोरम	870.00	सू० न०
17.	नागालैंड	122.38	सू० न०
18.	उड़ीसा	4208.00	3842.85
19.	पंजाब	1159.50	1903.22
20.	राजस्थान	9583.00*	9309.00
21.	सिक्किम	383.87	सू० न०
22.	तमिलनाडु	4640.70	5111.08
23.	त्रिपुरा	1158.04	सू० न०
24.	उत्तर प्रदेश	6790.16	9174.84
25.	पश्चिम बंगाल	सू० न०	3618.21
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	116.25	112.97
27.	चंडीगढ़	30.00	32.00
28.	दादर व नगर हवेली	97.20	137.97
29.	दमन और दिव	13.00	15.00
30.	दिल्ली	218.00	193.25
31.	लक्षद्वीप	16.00	16.00
32.	पांडिचेरी	91.33	55.50
	योग :	74262.56	70434.32

* संशोधित ।

सू० न०—सूचित नहीं किया गया है ।

वन क्षेत्रों के अतिक्रमणों का व्यवस्थापन

1060. श्री कैलाश नारायण सारंग : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन क्षेत्रों के अतिक्रमणों के व्यवस्थापन से संबंधित सरकार के क्या आदेश हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वन क्षेत्रों में किए गए अतिक्रमणों के व्यवस्थापन के मामले में कतिपय प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वन भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने के संबंध में मंत्रालय द्वारा 18-9-1990 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं । इन दिशा-निर्देशों के अनुसार वन भूमि पर 25-10-1980 से पहले किए गए अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए विचार किया जा सकता है बशर्ते कि कतिपय मानदण्ड पूरे किए जा रहे हों ।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अवैध कब्जों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत नियमित करने के लिए 2.73 लाख हैक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने के प्रस्ताव भेजे थे । प्रस्ताव की जांच करने के बाद मंत्रालय ने पात्र कब्जाधारियों के हक में अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए 1.03 लाख हैक्टेयर वन भूमि मंजूर की है ।

वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जाना

1061. श्री कैलाश नारायण सारंग : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने से संबंधित कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और अभी तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है; और

(ग) क्या सरकार ने वन ग्रामों को नियमित करने के लिए राज्य प्रशासन को प्राधिकृत किया है जबकि वन संरक्षण अधिनियमों को लागू होने से पूर्व ही वन ग्रामों की स्थापना हो चुकी थी और इस अधिनियम के लागू करने से पूर्व ही इनका गैर वानिकी उपयोग आरंभ हो चुका था ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) मंत्रालय द्वारा 18-9-1990 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अन्तर्गत अपेक्षित वन भूमि की अधिसूचना को रद्द करने के बाद वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदला जा सकता है ।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 216 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने के लिए 10 प्रस्ताव भेजे हैं । सभी 10 प्रस्तावों के बारे में राज्य सरकार से आवश्यक सूचना मांगी गई है, जो अभी नहीं मिली है ।

(ग) जी नहीं । वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने के लिए वन भूमि को औपचारिक रूप से अन्तरित/अनारक्षित करने से पूर्व वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी अपेक्षित है ।

Clearance to the Pooyamkutty Hydel Power Project in Kerala

1062. SHRI N. E. BALARAM : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had denied clearance to the Pooyamkutty Hydel Power Project in Kerala;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the State Government has requested the Centre to reconsider the decision and give clearance to the project considering the importance of the project to the state; and

(d) if so, the details and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) The Pooyamkutty project was accorded environmental clearance in June, 1985 subject to implementation of various safeguard measures. The proposal, however, was rejected under the Forest (Conservation) Act, 1980 in January, 1991 as the benefits from the project were not found to be commensurate with the likely environmental and ecological losses.

(c) and (d) Kerala State Government has requested for review of the proposal and it is under consideration whether the project could be modified to reduce environmental degradation.

Programme for Saving Nilgiri Hills

1063. SHRI M. A. BABY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) what are the Government's plans for saving Nilgiri hills from decaying further; and

(b) what is the achievement made so far?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) A series of measures have been initiated by the Central as well as the State Governments to save Nilgiri hills. These include:

— Establishment of a Nilgiri Biosphere Reserve which has protected a total of 5,200 sq. kms area. Under this programme, an amount of Rs. 291.18 lakhs has been so far released for management of Nilgiri Biosphere Reserves. The activities carried out include Survey and demarcation, Protection, Eco-development, Demonstration projects, Education and training etc.

— Hill area development programme which has undertaken extensive soil and water conservation works, as well as given rigorous protection to many patches of sholo vegetation.

— Nilgiris Private Tree Protection Act which has regulated all tree cutting on private lands; and

— Building construction in these hills is regulated strictly under the provisions of the specific legal enactments.

Hunting in Hastinapur Sanctuary

1064. SHRI CHATURANAN MISHRA
SHRI GURUDAS DASGUPTA

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a group of persons armed heavily were caught redhanded on 24th January, 1993 for intruding into the Hastinapur Swamp Deer Sanctuary near Muzzafaranagar and hunting throughout the night;

(b) if so, who were the persons caught; the extent demage and the number of animals killed; and

(c) what legal action was taken against them for violating the penal and Wild-laws?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) to (c) The staff of Hastinapur Wildlife Sanctuary alongwith the Police of Mirapur Police Station apprehended seven persons who were allegedly involved in poaching of wild animals in the sanctuary in the night of 23rd/24th January, 1993.

As per report received from the Chief Wildlife Warden, Government of Uttar Pradesh, one hog deer, 3 rabbits and a bag containing the skin of wild animals were seized. A case has been registered against the alleged offenders with the Police and matter is now in the Court of Law.

Denudation of the Ridge

1065. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Delhi Development Authority is ill-equipped to arrest denudation of the ridge;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government have any plan to check the denudation of the ridge?